

HINDI FILE



SIX SIGMA IAS

Dream | Dare | Deliver



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 22, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

प्रश्न 1. अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी की शुरुआत के दौरान भारत में राजनीतिक नियंत्रण के ब्रिटिश विस्तार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सहायक संधि (Subsidiary Alliance) प्रणाली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भारतीय शासक के क्षेत्र को अनिवार्य रूप से हड़पे बिना उसके विदेशी मामलों पर निर्णायक प्रभाव डालने में सक्षम बनाया।
2. सहायक संधि प्रणाली के तहत, भारतीय शासक को आम तौर पर एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने की आवश्यकता होती थी ताकि ब्रिटिश अंतर-राज्यीय विवादों में सीधे शामिल होने से बच सकें।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है? (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: कथन 1 सही है। विशेष रूप से लॉर्ड वेलेज़ली से जुड़ी सहायक संधि प्रणाली के तहत, भारतीय शासकों ने अपने क्षेत्रों के भीतर ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती को स्वीकार किया और बाहरी संबंधों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण छोड़ दिया। इसलिए इस व्यवस्था ने कंपनी को तत्काल क्षेत्रीय विलय के बिना राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने की अनुमति दी।

कथन 2 गलत है। इस प्रणाली की एक मौलिक विशेषता ठीक इसके विपरीत थी: सहयोगी शासक ने विदेशी संबंधों पर स्वतंत्र नियंत्रण छोड़ दिया और वह अन्य शक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत नहीं कर सकता था। इस प्रकार, संधि ने शासक की कूटनीतिक स्वायत्तता को संरक्षित करने के बजाय सीमित कर दिया।

परिणामस्वरूप इस प्रणाली ने कई औपचारिक रूप से स्वतंत्र भारतीय राज्यों को कंपनी के अधीनस्थ सहयोगियों में बदल दिया।

प्रश्न 2. पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सटीक रूप से बताता है कि जैविक आवर्धन (biomagnification) आमतौर पर उच्च पोषण स्तरों (trophic levels) पर अधिक स्पष्ट क्यों होता है?

- (a) उच्च पोषण स्तर वाले जीव हमेशा निचले पोषण स्तर वाले जीवों की तुलना में अधिक मात्रा में भोजन का उपभोग करते हैं।
- (b) स्थायी पदार्थ जिनका चयापचय या उत्सर्जन ठीक से नहीं हो पाता है, वे जीवों में जमा हो सकते हैं और क्रमिक पोषण हस्तांतरण के माध्यम से तेजी से केंद्रित हो सकते हैं।
- (c) पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण के कारण प्रदूषक रासायनिक रूप से अधिक विषैले पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं।
- (d) प्राथमिक उत्पादक अपने उपभोक्ताओं के बायोमास के आनुपातिक मात्रा में प्रदूषकों को चुनिंदा रूप से अवशोषित करते हैं।

उत्तर: (b)

व्याख्या: जैविक आवर्धन (बायोमैग्निफिकेशन) से तात्पर्य क्रमिक रूप से उच्च पोषण स्तरों पर कुछ स्थायी संदूषकों की सांद्रता में वृद्धि से है। कुछ ऑर्गेनोक्लोरीन यौगिकों और मिथाइलमर्करी जैसे पदार्थ क्षरण या प्रभावी उत्सर्जन का विरोध कर सकते हैं और इसलिए जीवों के भीतर जमा हो जाते हैं।

एक शिकारी अपने जीवनकाल के दौरान कई दूषित शिकारों का उपभोग कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके ऊतकों में व्यक्तिगत शिकार जीवों की तुलना में अधिक संदूषक सांद्रता हो सकती है।

विकल्प (a) एक आवश्यक शर्त नहीं है क्योंकि जैविक आवर्धन केवल भोजन की मात्रा के बजाय संदूषक गुणों और पोषण हस्तांतरण पर निर्भर करता है। विकल्प (c) गलत तरीके से इस प्रक्रिया का श्रेय ऊर्जा हस्तांतरण को देता है, जबकि विकल्प (d) पोषण स्तरों में प्रगतिशील एकाग्रता की व्याख्या नहीं करता है।

प्रश्न 3. एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के कामकाज के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में वृद्धि, अन्य बातें समान रहने पर, वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता को कम कर सकती है।
2. नीतिगत ब्याज दर (policy interest rate) में वृद्धि उधार लेने को अपेक्षाकृत अधिक महंगा बनाकर समग्र मांग को प्रभावित कर सकती है।
3. किसी अर्थव्यवस्था के आरक्षित धन (reserve money) में वृद्धि का परिणाम अनिवार्य रूप से व्यापक धन (broad money) में समान आनुपातिक वृद्धि के रूप में होता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: कथन 1 सही है। नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में वृद्धि के लिए बैंकों को अपनी जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा भंडार के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिससे अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर ऋण देने के लिए संभावित रूप से उपलब्ध धनराशि कम हो जाती है।

कथन 2 सही है। एक उच्च नीतिगत ब्याज दर संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में उधार लेने की लागत बढ़ा सकती है और इस प्रकार उपभोग तथा निवेश मांग के ब्याज-संवेदनशील घटकों को नियंत्रित कर सकती है।

कथन 3 गलत है। आरक्षित धन और व्यापक धन में यांत्रिक रूप से निश्चित 1:1 आनुपातिक संबंध नहीं होता है। व्यापक धन का अंतिम विस्तार बैंकों के ऋण देने के व्यवहार, मुद्रा प्राथमिकताओं और आरक्षित आवश्यकताओं जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

प्रश्न 4. भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित भारतीय संवैधानिक ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन अपने निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन (review) कर सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

3. भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को उसकी सलाहकारी राय (advisory opinion) के लिए संदर्भित कर सकता है।
4. अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकारी राय में ठीक वही बाध्यकारी शक्ति होती है जो एक सामान्य प्रतिकूल कार्यवाही (ordinary adversarial proceeding) में दिए गए फैसले में होती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (c)

व्याख्या: कथन 1 सही है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को संसदीय कानून और अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन अपने द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन करने का अधिकार देता है।

कथन 2 सही है। अनुच्छेद 141 यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। यह सर्वोच्च न्यायालय के घोषित कानून के पूर्ववर्ती प्राधिकार (precedential authority) को स्थापित करता है।

कथन 3 सही है। अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति कुछ प्रश्नों को सर्वोच्च न्यायालय को उसकी सलाहकारी राय के लिए संदर्भित कर सकता है, जिसमें सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के प्रश्न शामिल हैं।

कथन 4 गलत है। अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी राय संवैधानिक रूप से किसी विवादित कार्यवाही में सामान्य फैसले से अलग होती है। इसमें केवल वह समान बाध्यकारी चरित्र नहीं होता है जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद 141 के तहत अदालत के न्यायिक निर्धारण के माध्यम से "घोषित कानून" के लिए की गई है। अतः तीन कथन सही हैं।

प्रश्न 5. निम्नलिखित अभिकथन और दो कारणों पर विचार कीजिए:

अभिकथन (A): विश्व में जनसंख्या का स्थानिक वितरण अत्यधिक असमान है। **कारण 1 (R1):** जलवायु, उच्चावच (relief), मिट्टी, जल की उपलब्धता और आर्थिक अवसरों के अनुकूल संयोजन वाले क्षेत्र जनसंख्या की बड़ी सांद्रता को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होते हैं। **कारण 2 (R2):** मानव जनसंख्या केवल उन्हीं क्षेत्रों में विस्तारित हो सकती है जहाँ प्राकृतिक पर्यावरणीय स्थितियाँ पूरे वर्ष समान रूप से अनुकूल हों।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) R1 और R2 दोनों सही हैं, और दोनों A की व्याख्या करते हैं
- (b) R1 और R2 दोनों सही हैं, लेकिन केवल R1, A की व्याख्या करता है
- (c) R1 सही है, लेकिन R2 गलत है, और R1, A की व्याख्या करता है
- (d) R1 गलत है, लेकिन R2 सही है, और R2, A की व्याख्या करता है

उत्तर: (c)

व्याख्या: अभिकथन सही है: जनसंख्या वितरण अत्यधिक असमान है क्योंकि भौतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक कारक पूरे अंतरिक्ष में काफी भिन्न होते हैं।

कारण 1 सही है और सीधे अभिकथन की व्याख्या करता है। अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों और सुलभ आर्थिक अवसरों वाले क्षेत्रों ने ऐतिहासिक रूप से घनी बस्तियों का समर्थन किया है। हालाँकि, अनुकूल परिस्थितियाँ परिपूर्ण या समान होने की आवश्यकता नहीं हैं; तकनीकी विकास मानव आबादी को उन वातावरणों में रहने की अनुमति दे सकता है जो भौतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं।

कारण 2 इसलिए गलत है। मानव निवास केवल उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है जहाँ पूरे वर्ष समान रूप से अनुकूल प्राकृतिक स्थितियाँ होती हैं। उदाहरणों में उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, रेगिस्तान, पहाड़ और अन्य पर्यावरणीय रूप से मांग वाले क्षेत्र शामिल हैं जहाँ प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुकूलन ने पर्याप्त मानव बस्ती को सक्षम बनाया है।

दैनिक अभ्यास प्रश्न – करंट अफेयर्स अनुभाग से

प्रश्न 1. अभ्यास वीर गार्जियन-2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अभ्यास भारतीय वायु सेना और जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, जिसका 2026 संस्करण जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है।
2. जापान के F-2A विमान की भागीदारी का महत्व प्लेटफॉर्म परिचितता से परे है, क्योंकि विमान का एयरफ्रेम वंशक्रम (lineage) अमेरिका के F-16 से जुड़ा हुआ है, जिससे केवल भारत के रूसी-मूल के लड़ाकू प्लेटफॉर्मों वाले अभ्यासों से भिन्न एक परिचालन संदर्भ प्राप्त होता है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर:

- (c)

व्याख्या:

दोनों कथन सही हैं। वीर गार्जियन-2026 भारतीय वायु सेना (IAF) और जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JASDF) के बीच एक द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है, जो 9-22 सितंबर 2026 तक वायु सेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया गया है। भारतीय वायु सेना के घटक में तेजस, सु-30MKI और राफेल शामिल हैं, जबकि जापान ने F-2A लड़ाकू विमानों को तैनात किया है।

F-2A विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि इसका डिज़ाइन F-16 परिवार से लिया गया है। इस प्रकार, यह अभ्यास भारत द्वारा संचालित रूसी-मूल के सु-30MKI से भिन्न एक प्लेटफॉर्म वंशक्रम को शामिल करते हुए सामरिक अनुभव प्रदान करता है। इस अभ्यास में मिशन नियोजन, इंजीनियरिंग आदान-प्रदान, एयरोस्पेस-सुरक्षा सहभागिता और परिचालन डिब्रीफिंग भी शामिल हैं, जो अंतर-संचालनीयता को केवल एक साथ उड़ान भरने की तुलना में अधिक व्यापक बनाते हैं।

यहाँ जाल द्विपक्षीय वायु अंतर-संचालनीयता को बहुपक्षीय या संधि-आधारित सामूहिक-रक्षा अभ्यास के साथ भ्रमित करने में निहित है। वीर गार्जियन स्वयं एक द्विपक्षीय भारत-जापान अभ्यास है।

प्रश्न 2. हाल ही में समाचारों में रहा 'कलिंग रत्न पुरस्कार', 'सरला सम्मान' से सबसे बेहतर तरीके से किस प्रकार भिन्न है?

- (a) पहला भारत सरकार द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार है, जबकि दूसरा ओडिशा सरकार द्वारा स्थापित एक राज्य नागरिक पुरस्कार है।
- (b) पहला कटक स्थित सरला साहित्य संसद द्वारा ओडिशा से जुड़े विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि दूसरा मुख्य रूप से उड़िया साहित्य में विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है।
- (c) पहला केवल सेवारत संवैधानिक अधिकारियों तक सीमित है, जबकि दूसरा केवल सेवानिवृत्त लोक सेवकों तक सीमित है।
- (d) पहला ओडिशा विधानसभा द्वारा दिया जाता है, जबकि दूसरा साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है।

उत्तर:

(b)

व्याख्या:

कलिंग रत्न पुरस्कार कटक स्थित एक साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन **सरला साहित्य संसद** द्वारा स्थापित और प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित क्षेत्रीय सम्मान है। यह ओडिशा से उत्पन्न होने वाले या उससे गहराई से जुड़े उन प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को मान्यता देता है जिनके योगदान ने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व हासिल किया है।

वर्ष 2026 में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कलिंग रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। उसी समारोह में, उड़िया साहित्य में योगदान के लिए साहित्यकार डॉ. रामचंद्र बेहरा को सरला सम्मान से सम्मानित किया गया।

इसलिए महत्वपूर्ण अंतर संस्थागत और कार्यात्मक है: कलिंग रत्न ओडिशा से जुड़ी प्रतिष्ठित उपलब्धि की एक व्यापक मान्यता है, जबकि सरला सम्मान मुख्य रूप से साहित्यिक उपलब्धि से जुड़ा हुआ है।

प्रश्न 3. ओआरवी सागर मंथन (ORV Sagar Manthan) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे एक बहुविषयक गहरे समुद्र अनुसंधान पोत के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो वायुमंडल से लेकर समुद्र तल तक फैले अवलोकनों का समर्थन करने में सक्षम है।
2. इसकी वैज्ञानिक क्षमताओं में बाथिमेट्रिक मैपिंग, भूकंपीय-प्रतिबिंब (seismic-reflection) अध्ययन, CTD अवलोकन और दूरस्थ रूप से संचालित या स्वायत्त अंडरवाटर सिस्टम की तैनाती शामिल है।
3. इसका मुख्य जनादेश भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर खनिज अन्वेषण तक ही सीमित है, जिसमें जलवायु और महासागरीय अनुसंधान केवल प्रासंगिक अनुप्रयोग हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक

- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर:

- (b)

व्याख्या:

कथन 1 और 2 सही हैं। ORV सागर मंथन दक्षिण महासागर सहित मांग वाले समुद्री वातावरण में संचालन के लिए विकसित एक सर्व-मौसम, बहुविषयक गहरा समुद्र अनुसंधान पोत है। इसे महासागरीय और वायुमंडलीय अवलोकनों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसके उपकरणों में डायनेमिक पोजिशनिंग, स्वाथ मल्टीबीम बाथिमेट्री, मल्टीचैनल सीस्मिक्स रिफ्लेक्शन सिस्टम, सब-बॉटम प्रोफाइलर, मौसम विज्ञान रडार और CTD अवलोकन क्षमता शामिल हैं। यह ROVs, AUVs और गहरे समुद्र के तलछट कोरर्स (benthic corers) की तैनाती और पुनर्प्राप्ति का भी समर्थन कर सकता है।

कथन 3 गलत है क्योंकि खनिज अन्वेषण इसके जनादेश का केवल एक घटक है। पोत का उद्देश्य जलवायु, मानसून, सुनामी और व्यापक महासागरीय अनुसंधान में योगदान देना भी है। यह डीप ओशन मिशन के तहत वर्टिकल-4 (गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण) से जुड़ा हुआ है।

वैचारिक जाल डीप ओशन मिशन को केवल गहरे समुद्र में खनिज निष्कर्षण के समान मानना है; पोत की वैज्ञानिक भूमिका काफी व्यापक है।

प्रश्न 4. लद्दाख से संबंधित प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह प्रस्ताव लद्दाख को राज्य में परिवर्तित किए बिना भाग XXI के तहत एक विशेष संवैधानिक व्यवस्था शुरू करने का प्रयास करता है।
2. प्रस्तावित प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय के पास भूमि, संपत्ति हस्तांतरण, संस्कृति, भाषा, वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित कुछ मामलों पर विधायी क्षमता होगी।
3. यह प्रस्ताव स्वतः ही लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत उपलब्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा।
4. प्रस्तावित ढांचा, जैसा कि वर्तमान में वर्णित है, वित्तीय स्वायत्तता के प्रश्न को हल करता है और पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था को पूरी तरह से प्रस्तावित निर्वाचित निकाय के तहत रखता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर:

(b)

व्याख्या:

कथन 1 और 2 सही हैं। प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) को लद्दाख के लिए भाग XXI के तहत एक विशिष्ट (sui generis) संवैधानिक व्यवस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए बिना, निर्दिष्ट संवेदनशील विषयों पर विधायी शक्तियों के साथ एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय शासी निकाय स्थापित करने का प्रयास करता है।

कथन 3 गलत है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अनुकूलित संवैधानिक सुरक्षा उपाय तैयार करना है और यह स्वतः छठी अनुसूची का दर्जा प्रदान नहीं करता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होने वाला एक विशिष्ट संवैधानिक ढांचा है।

कथन 4 भी गलत है। वित्तीय स्वायत्तता, बजटीय व्यवस्था, कार्यकारी अधिकार और पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था पर नियंत्रण उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बने हुए हैं जिनका सटीक विवरण स्रोत द्वारा वर्णित प्रस्ताव में तय नहीं किया गया है।

जाल "मौजूदा विशेष प्रावधानों से प्रेरणा लेने" और "उन प्रावधानों को पूर्ण रूप से स्वतः आयात करने" के बीच अंतर न समझ पाना है। प्रस्तावित मॉडल को अनुकूलित और विशिष्ट (sui generis) के रूप में वर्णित किया गया है।

प्रश्न 5. निम्नलिखित अभिकथन और दो कारणों पर विचार कीजिए:

अभिक्रिया (A): ओरेंगुटान (orangutans) का पारिस्थितिक महत्व एक संकटग्रस्त प्राइमेट के रूप में उनकी स्थिति से परे फैला हुआ है क्योंकि उनकी आबादी में बदलाव का प्रभाव वन पुनरुद्धार (forest regeneration) पर पड़ सकता है।

कारण 1 (R1): ओरेंगुटान मुख्य रूप से फलभक्षी (frugivorous) होते हैं और उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी प्रणालियों में बीजों के प्रकीर्णन (dispersal) में योगदान करते हैं।

कारण 2 (R2): ओरेंगुटान मुख्य रूप से स्थलीय स्तनधारी हैं जिनकी मुख्य पारिस्थितिक भूमिका चराई और शाकीय वनस्पतियों के दमन से उत्पन्न होती है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) R1 और R2 दोनों सही हैं, और दोनों A की व्याख्या करते हैं
- (b) R1 और R2 दोनों सही हैं, लेकिन केवल R1, A की व्याख्या करता है
- (c) R1 सही है, लेकिन R2 गलत है, और R1, A की व्याख्या करता है
- (d) R1 गलत है, लेकिन R2 सही है, और R2, A की व्याख्या करता है

उत्तर:

(c)

व्याख्या:

अधिकथन सही है। ओरेंगुटान उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण घटक हैं, विशेष रूप से क्योंकि उनके भोजन का व्यवहार बीज प्रकीर्णन और वन पुनरुद्धार में योगदान देता है।

कारण 1 सही है। ओरेंगुटान मुख्य रूप से फलभक्षी होते हैं, जो अन्य खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ वन फलों की एक विस्तृत विविधता का उपभोग करते हैं। वन आवासों के माध्यम से उनकी आवाजाही और फलों का सेवन बीजों के प्रकीर्णन को सुविधाजनक बनाता है, जिससे वे वन पारिस्थितिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण एजेंट बन जाते हैं।

कारण 2 गलत है। ओरेंगुटान मुख्य रूप से स्थलीय होने के बजाय अत्यधिक वृक्षवासी (arboreal) होते हैं। वे अपना अधिकांश जीवन पेड़ों की छत्रछाया (canopy) में बिताते हैं और उनके पास लंबे, शक्तिशाली हाथ और पकड़ने वाले पैर जैसे रूपात्मक अनुकूलन होते हैं जो पेड़ों के माध्यम से आवाजाही के लिए अनुकूल होते हैं।

सामयिकी (Current affairs) का संदर्भ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ओडिशा में बचाए गए ओरेंगुटानों की पहचान बोर्नियो और सुमात्रा की स्थानिक प्रजातियों के समूह से संबंधित होने के रूप में की गई थी, न कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली भारतीय प्रजातियों के रूप में। ओरेंगुटान की तीनों मान्यता प्राप्त प्रजातियाँ—बोर्नियन, सुमात्राण और तपानुलि—गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध हैं।

प्रश्न 6. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

पर्वत/चोटी	भौगोलिक संबंध
1. गाशरब्रम I (Gasherbrum I)	काराकोरम
2. गाशरब्रम II (Gasherbrum II)	बाल्टोरो ग्लेशियर क्षेत्र
3. गाशरब्रम मैसिफ (Gasherbrum Massif)	भारत-नेपाल सीमा
4. गाशरब्रम I (Gasherbrum I)	इसे 'हिडन पीक' भी कहा जाता है

उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर:

- (c)

व्याख्या:

युग्म 1, 2 और 4 सही सुमेलित हैं।

गाशरब्रम I काराकोरम का हिस्सा है और इसे हिडन पीक (Hidden Peak) के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 8,080 मीटर तक उगता है और चीन-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में स्थित है।

गाशरब्रम II भी काराकोरम में गाशरब्रम मैसिफ का एक सदस्य है और ऊपरी बाल्टोरो ग्लेशियर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह एक 8,000-मीटर की चोटी है और ऐतिहासिक रूप से इसे K4 नाम दिया गया था।

युग्म 3 गलत है। गाशरब्रम मैसिफ भारत-नेपाल सीमा के बजाय काराकोरम से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से बाल्टोरो ग्लेशियर के उत्तर-पूर्वी छोर के आसपास का क्षेत्र। यह मैसिफ व्यापक चीन-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में स्थित है।

मानचित्र-आधारित जाल: गाशरब्रम को मानसिक रूप से पश्चिमी हिमालय के काराकोरम क्षेत्र में स्थित होना चाहिए, न कि भारत-नेपाल हिमालयी क्षेत्र के साथ।

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

GS पेपर I — कला और संस्कृति

प्रश्न:

“भारतीय मंदिर वास्तुकला को नागरा, द्रविड़ और वेसरा शैलियों में एक कठोर वर्गीकरण के बजाय क्षेत्रीय अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में बेहतर समझा जाता है।” उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

नमूना उत्तर

भारतीय मंदिर वास्तुकला भारत की सभ्यतागत विविधता की सबसे स्थायी अभिव्यक्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। एनसीईआरटी की 'एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट भाग-I', अध्याय 6, मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला, स्वयं नागरा, द्रविड़ और वेसरा श्रेणियों को पूरी तरह से अलग-अलग वास्तुशिल्पीय खंडों के रूप में मानने के खिलाफ चेतावनी देता है। मंदिरों का विकास धर्म, भूगोल, सामग्री की उपलब्धता, संरक्षण और क्षेत्रीय निर्माण परंपराओं के बीच बातचीत को दर्शाता है।

वर्गीकरण से निरंतरता तक

पारंपरिक वर्गीकरण मोटे तौर पर पहचान करता है:

- नागरा — मुख्य रूप से उत्तरी भारत, जो गर्भगृह के ऊपर एक घुमावदार शिखर की विशेषता है।
- द्रविड़ — मुख्य रूप से दक्षिणी भारत, जो एक पिरामिडनुमा विमान, प्राचीर दीवारों और प्रमुख प्रवेश द्वारों की विशेषता है।
- वेसरा — अक्सर संकरित वास्तुशिल्पीय प्रवृत्तियों के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से दक्कन में।

हालाँकि, इन श्रेणियों को जलरोधी भौगोलिक बक्सों के बजाय विश्लेषणात्मक ढाँचे के रूप में माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, दक्कन वास्तुशिल्पीय संपर्क का एक क्षेत्र बन गया। चालुक्य और बाद की होयसला परंपराएं उत्तरी और दक्षिणी वास्तुशिल्पीय शब्दावली के संयोजन को दर्शाती हैं। बेलूर और हलेबिडू में होयसला मंदिर, अपनी जटिल योजनाओं, समृद्ध रूप से नक्काशीदार सतहों और विशिष्ट मंचों के साथ, केवल उन्हें एक ही पाठ्यपुस्तक श्रेणी में निर्दिष्ट करके पर्याप्त रूप से नहीं समझे जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अनुकूलन

क्षेत्रीय भूगोल ने वास्तुशिल्पीय विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

ओडिशा में, मंदिरों में रेखा देउल और पीढ़ा देउल जैसी विशिष्ट विशेषताएं विकसित हुईं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागरा परंपरा के एक अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रीय रूप में विस्तार को दर्शाता है।

मध्य भारत में, खजुराहो गुच्छित ऊर्ध्वाधर रूपों, विस्तृत मूर्तिकला कार्यक्रमों और ऊंचे मंचों के माध्यम से नागरा परंपरा के विकास को प्रदर्शित करता है।

तमिल क्षेत्र में, बृहदेश्वर जैसे चोल मंदिर विशाल विमानों और तेजी से विस्तृत होते मंदिर परिसरों के साथ द्रविड़ वास्तुकला के स्मारकीय विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हालाँकि, दक्कन यह प्रदर्शित करता है कि कठोर वर्गीकरण समस्याग्रस्त क्यों हो जाता है। चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसला और अन्य शक्तियों के बीच राजनीतिक अंतःक्रियाओं ने वास्तुशिल्पीय प्रयोगों को सुगम बनाया। एलोरा का कैलाश मंदिर, यद्यपि मूल रूप से अवधारणा में द्रविड़ है, दक्कन में वास्तुशिल्पीय अंतःक्रिया के एक व्यापक वातावरण के भीतर उकेरा गया था।

एक सामाजिक-आर्थिक संस्था के रूप में मंदिर

मंदिर केवल धार्मिक संरचनाएं नहीं थे। वे बन गए:

- अनुष्ठान गतिविधियों के केंद्र;
- मूर्तिकला और चित्रकला के भंडार;
- कारीगरों के नियोक्ता;
- भूमि अनुदान प्राप्तकर्ता;
- संगीत और नृत्य के केंद्र;
- आर्थिक पुनर्वितरण के केंद्र;
- और, कई अवधियों में, महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थान।

इस प्रकार, मंदिर वास्तुकला उस अवधि की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन के पुनर्निर्माण के लिए साक्ष्य भी प्रदान करती है।

इसलिए, नागरा, द्रविड़ और वेसरा उपयोगी वैचारिक श्रेणियां हैं, लेकिन भारतीय मंदिर वास्तुकला निरंतर क्षेत्रीय प्रयोगों और सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से विकसित हुई है। इसकी विविधता भारत के भौगोलिक बहुलवाद के साथ-साथ कारीगरों, विचारों, धार्मिक प्रथाओं और राजनीतिक संरक्षण की आवाजाही को दर्शाती है। मंदिरों को स्थिर शैलीगत खंडों के बजाय गतिशील क्षेत्रीय परंपराओं के रूप में समझना भारतीय कला और वास्तुकला की अधिक ऐतिहासिक रूप से सटीक व्याख्या प्रदान करता है।

GS पेपर II — भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

Q2. “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा केवल उसकी राष्ट्रीय क्षमताओं पर ही नहीं, बल्कि मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था के प्रतिनिधित्व घाटे पर भी आधारित है।” परीक्षण कीजिए। सुरक्षा परिषद के सुधार में कौन सी संरचनात्मक और राजनीतिक बाधाएं बनी हुई हैं?

नमूना उत्तर

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सत्ता के वितरण को प्रतिबिंबित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालाँकि, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में गहन जनसांख्यिकीय, आर्थिक और भू-राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप, यूएनएससी सुधार पर बहस में केवल स्थायी सदस्यता के लिए भारत की आकांक्षा ही शामिल नहीं है, बल्कि वैश्विक शासन के प्रतिनिधित्व, वैधता और प्रभावशीलता का बड़ा प्रश्न भी शामिल है।

भारत ने सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार का लगातार समर्थन किया है, जिसमें स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार शामिल है। भारत के आधिकारिक रुख ने अंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया के भीतर पाठ-आधारित वार्ताओं की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

भारत का पक्ष

भारत के तर्क को कई आयामों के माध्यम से समझा जा सकता है।

पहला, जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व।

भारत मानवता के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी स्थायी सदस्यता संरचना अनिवार्य रूप से 1945 की भू-राजनीतिक परिस्थितियों की ही उपज बनी हुई है।

दूसरा, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में योगदान।

भारत ने ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बहुपक्षीय कूटनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

तीसरा, आर्थिक और रणनीतिक महत्व।

भारत का बढ़ता आर्थिक वजन और वैश्विक शासन में विस्तार से होती भूमिका उसके इस तर्क को मजबूत करती है कि समकालीन संस्थानों को वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

चौथा, विकासशील दुनिया का प्रतिनिधित्व।

भारत खुद को विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में प्रस्तुत करता है, और यह तर्क देता है कि मौजूदा संरचना उनके हितों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है।

G4 समूह—भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील—ने संयुक्त रूप से स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में परिषद के विस्तार की वकालत की है।

सुधार कठिन क्यों बना हुआ है

मुख्य कठिनाई यह है कि यूएनएससी सुधार स्वयं एक राजनीतिक सहमति पर निर्भर है जिसमें वे राज्य शामिल हैं जिनके संस्थागत विशेषाधिकार संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

वीटो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्थायी सदस्यता से जुड़ा कोई भी सुधार अनिवार्य रूप से प्रश्न उठाता है:

- क्या नए स्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिलनी चाहिए;
- क्या मौजूदा वीटो शक्तियों को संशोधित किया जाना चाहिए;
- क्या अंततः वीटो को समाप्त कर दिया जाना चाहिए;
- और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए।

दूसरी समस्या क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा है। अलग-अलग क्षेत्र इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि किस राज्य को स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

तीसरा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संशोधन तंत्र से संबंधित है, जो संरचनात्मक सुधार को साधारण महासभा के फैसले की तुलना में काफी अधिक कठिन बनाता है।

चौथी बाधा विभिन्न सुधार गठबंधनों के बीच मतभेद है। G4 स्थायी सीटें चाहता है, जबकि 'यूनाइटींग फॉर कंसेंसस' समूह ने ऐतिहासिक रूप से नए स्थायी सदस्यों के बजाय मुख्य रूप से गैर-स्थायी या दीर्घकालिक निर्वाचित सीटों के माध्यम से विस्तार का पक्ष लिया है।

आगे का रास्ता

एक व्यावहारिक सुधार प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होगी:

- पाठ-आधारित वार्ता;
- परिषद की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता;
- बेहतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व;
- वैधता के साथ प्रभावशीलता को संतुलित करना;
- वीटो संयम पर चर्चा;
- विकासशील देशों का अधिक प्रतिनिधित्व।

निष्कर्ष

इसलिए यूएनएससी पर भारत के दावे के दो परस्पर जुड़े आयाम हैं: राष्ट्रीय उम्मीदवारी और संस्थागत सुधार। गहरा मुद्दा यह है कि क्या 1945 की भू-राजनीतिक संरचना के लिए बनाई गई परिषद काफी हद तक परिवर्तित बीसवीं-

इक्कीसवीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वैधता बनाए रख सकती है। सार्थक सुधार के लिए विस्तार को केवल राजनयिक विशेषाधिकार के पुनर्वितरण के रूप में देखने के बजाय निर्णय लेने की प्रभावशीलता के साथ प्रतिनिधित्व का तालमेल बिठाना होगा।

GS पेपर III — नैनोप्रौद्योगिकी

Q3. “नैनोप्रौद्योगिकी क्षेत्र-विशिष्ट प्रौद्योगिकी के बजाय एक सक्षम तकनीक है।” व्याख्या कीजिए। इसके संबंध जोखिमों को उजागर करते हुए, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, जल, ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण से संबंधित भारत की चुनौतियों का समाधान करने की इसकी क्षमता का परीक्षण कीजिए।

नमूना उत्तर

नैनोप्रौद्योगिकी में अत्यंत छोटे पैमाने पर पदार्थ का हेरफेर और अनुप्रयोग शामिल हैं, जहां सामग्री बड़े आयामों में देखे गए गुणों से काफी भिन्न गुण प्रदर्शित कर सकती है। इसका महत्व एक एकल औद्योगिक क्षेत्र का गठन करने में नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में सामग्री, उपकरणों और जैविक प्रणालियों के प्रदर्शन को संशोधित करने की इसकी क्षमता में निहित है।

भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नैनोसाइंस और नैनोप्रौद्योगिकी को स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा से लेकर पर्यावरण और कृषि तक के अनुप्रयोगों के साथ एक सक्षम क्षेत्र के रूप में माना है। नैनो मिशन 2007 में शुरू किया गया था और बाद में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में विकसित हुआ।

नैनोस्केल क्यों मायने रखता है

नैनोस्केल पर, सामग्री परिवर्तित गुण प्रदर्शित कर सकती है:

- सतह-क्षेत्र-से-आयतन अनुपात;
- विद्युत गुण;
- ऑप्टिकल व्यवहार;
- चुंबकीय विशेषताएं;
- उत्प्रेरक गतिविधि;
- यांत्रिक गुण।

यह विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए सामग्री को इंजीनियर करने के अवसर पैदा करता है।

स्वास्थ्य सेवा

नैनोप्रौद्योगिकी लक्षित दवा वितरण को आसान बना सकती है, जहां उपचारात्मक अणुओं को तरजीही रूप से विशेष ऊतकों या कोशिकाओं की ओर पहुंचाया जाता है।

संभावित लाभों में शामिल हैं:

- नियंत्रित दवा रिलीज;
- कम प्रणालीगत जोखिम;
- बेहतर नैदानिक संवेदनशीलता;
- नैनोसेंसर्स;
- इमेजिंग प्रौद्योगिकियां;
- रोगाणुरोधी सामग्री।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) समर्थित अनुसंधान में नैनो ड्रग-डिलीवरी सिस्टम और स्वास्थ्य सेवा अनुप्रयोगों के लिए नैनोमैटेरियल्स शामिल हैं।

कृषि

नैनोप्रौद्योगिकी इसमें योगदान दे सकती है:

- नैनो-सक्षम उर्वरक;
- नियंत्रित पोषक तत्व रिलीज;
- मिट्टी और फसल निगरानी के लिए नैनोसेंसर्स;
- लक्षित कृषि रसायन वितरण;
- जल-उपयोग दक्षता में सुधार।

महत्वपूर्ण चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि बड़ी हुई दक्षता मिट्टी और पानी में लगातार नैनोकणों के माध्यम से अप्रत्याशित पारिस्थितिक प्रभाव पैदा न करे।

जल सुरक्षा

संदूषकों को हटाने के लिए झिल्लियों और निस्पंदन प्रणालियों में नैनोमैटेरियल्स को शामिल किया जा सकता है। भारत के पूर्ववर्ती नैनो मिशन ने स्पष्ट रूप से सुरक्षित पेयजल को राष्ट्रीय प्रासंगिकता के क्षेत्र के रूप में पहचाना था। यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जल शोधन को तेजी से वहनीयता और विकेंद्रीकृत तैनाती के साथ तकनीकी दक्षता को जोड़ना होगा।

ऊर्जा

नैनोसंरचित सामग्रियों के निम्नलिखित क्षेत्रों में संभावित अनुप्रयोग हैं:

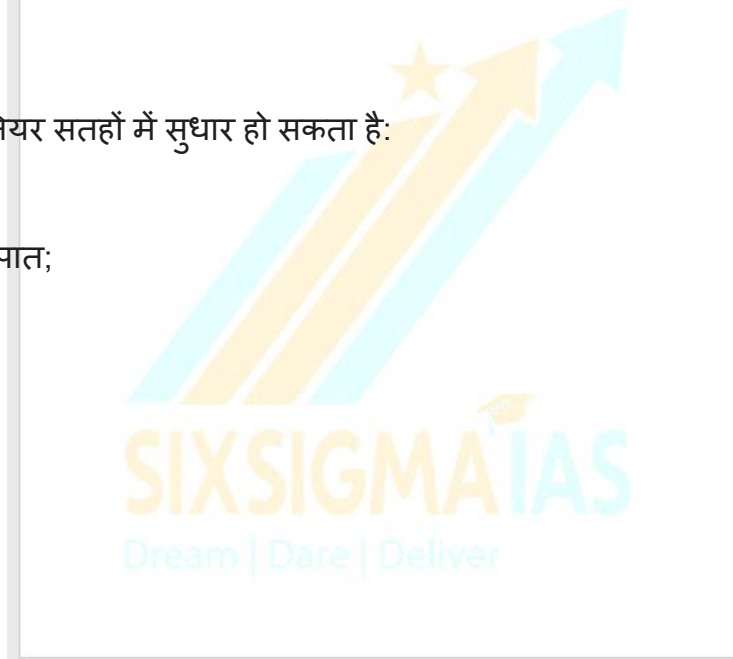
- बैटरी;
- सुपरकैपेसिटर;
- सौर सेल;
- उत्प्रेरक;
- हाइड्रोजन से संबंधित प्रौद्योगिकियां;
- ऊर्जा भंडारण।

नैनो मिशन के तहत DST अनुसंधान में लिथियम रीचार्जबल बैटरी के लिए नैनोसंरचित इलेक्ट्रोड सामग्री और नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए नैनोमैटेरियल्स शामिल थे।

उन्नत विनिर्माण

नैनोमैटेरियल्स और इंजीनियर सतहों में सुधार हो सकता है:

- शक्ति-से-भार अनुपात;
- घिसाव प्रतिरोध;
- संक्षारण प्रतिरोध;
- उत्प्रेरक दक्षता;
- सेंसिंग क्षमताएं।



इस प्रकार, नैनोप्रौद्योगिकी उन्नत विनिर्माण का एक सर्वव्यापी घटक बन सकती है।

जोखिम और शासन

वही गुण जो नैनोमैटेरियल्स को उपयोगी बनाते हैं, जोखिम भी उत्पन्न कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण चिंताओं में शामिल हैं:

- अनिश्चित विषाक्तता;
- व्यावसायिक जोखिम;
- पर्यावरणीय स्थिरता;

- जैवसंचयन;
- अपर्याप्त जीवन-चक्र मूल्यांकन;
- निपटान चुनौतियां;
- नियामक अंतर।

इसलिए एक प्रमुख प्रशासनिक चुनौती नवाचार-सावधानी का संतुलन है। विनियमन को अनावश्यक रूप से लाभकारी अनुसंधान को दबाना नहीं चाहिए, लेकिन वाणिज्यिक तैनाती के साथ जोखिम मूल्यांकन, मानक, जहां उपयुक्त हो लेबलिंग और जीवन-चक्र निगरानी होनी चाहिए।

निष्कर्ष

इसलिए नैनोप्रौद्योगिकी को कई क्षेत्रों को बदलने में सक्षम एक प्लेटफॉर्म तकनीक के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत की चुनौती प्रयोगशाला-स्तरीय उत्कृष्टता से किफायती और सुरक्षित वाणिज्यिक अनुप्रयोगों की ओर बढ़ने की है, साथ ही समानांतर नियामक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय विकसित करने की है। इसकी अंतिम सफलता केवल छोटी सामग्री बनाने पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि नैनोस्केल वैज्ञानिक ज्ञान को सामाजिक रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने पर निर्भर करेगी।

GS पेपर IV — नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक प्रशासन

Q4. एक जिला प्रशासक को पता चलता है कि एक कल्याणकारी योजना औपचारिक रूप से हर प्रक्रियात्मक आवश्यकता का पालन कर रही है, फिर भी इसके लाभ लक्षित लाभार्थियों के केवल एक छोटे हिस्से तक पहुंच रहे हैं क्योंकि आवेदन प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है और कमजोर नागरिकों के लिए अगम्य है। कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों का तर्क है कि “नियमों का पालन किया जा रहा है”। इसमें शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। प्रशासक को क्या करना चाहिए? सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, जवाबदेही, प्रतिक्रियाशीलता और प्रक्रियात्मक अनुपालन तथा सारभूत न्याय के बीच अंतर के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

नमूना उत्तर

यह मामला प्रक्रियात्मक वैधता और सारभूत न्याय के बीच एक मूलभूत नैतिक तनाव प्रस्तुत करता है। केवल निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने से यह गारंटी नहीं मिलती है कि सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। सार्वजनिक प्रशासन अंततः नागरिकों के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रतिबद्धताओं को सार्थक परिणामों में अनुवादित करने के लिए मौजूद है।

नैतिक मुद्दे

1. प्रक्रियात्मक अनुपालन बनाम सारभूत न्याय

अधिकारी इस आधार पर अपना बचाव कर रहे हैं कि स्थापित नियमों का पालन किया गया है। हालाँकि, यदि प्रक्रिया स्वयं अपवर्जन (बाहर करना) पैदा करती है, तो यांत्रिक अनुपालन कल्याणकारी कार्यक्रम के सारभूत उद्देश्य को कमजोर कर सकता है।

2. सहानुभूति

कमजोर नागरिकों में साक्षरता, डिजिटल पहुंच, दस्तावेज या प्रशासनिक परिचितता की कमी हो सकती है। एक नैतिक प्रशासक को गैर-पहुंच को नागरिक विफलता के रूप में मानने के बजाय इन बाधाओं को समझना चाहिए।

3. प्रतिक्रियाशीलता

सार्वजनिक प्रशासन को वास्तविक सामाजिक स्थितियों का जवाब देना चाहिए। यदि साक्ष्य दिखाते हैं कि पात्र नागरिक किसी योजना तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो अपरिवर्तित प्रक्रियाओं को केवल इसलिए जारी रखना क्योंकि वे औपचारिक रूप से वैध हैं, संस्थागत जड़ता को दर्शाता है।

4. जवाबदेही

जवाबदेही का विस्तार व्यय और कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर परिणामों तक होना चाहिए। एक प्रशासक को यह पूछना चाहिए कि क्या लक्षित लाभार्थियों को वास्तव में वे लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके लिए सार्वजनिक संसाधन आवंटित किए गए हैं।

5. सत्यनिष्ठा

सत्यनिष्ठा के लिए सार्वजनिक पद के उद्देश्य और प्रशासनिक आचरण के बीच संरेखण की आवश्यकता होती है। अधिकारी प्रक्रियात्मक शुद्धता को ढाल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते जब वे जानते हैं कि नीतिगत उद्देश्य विफल हो रहा है।

कार्रवाई का तरीका

प्रशासक को सबसे पहले एक साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन करना चाहिए:

- वास्तव में लाभ प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थियों के अनुपात की पहचान करना;
- विश्लेषण करना कि कहां आवेदन खारिज किए जा रहे हैं या छोड़ दिए जा रहे हैं;
- दस्तावेजीकरण और डिजिटल बाधाओं की पहचान करना;
- फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और लाभार्थी समूहों से परामर्श करना;
- यह जांचना कि क्या अपवर्जन जानबूझकर, संरचनात्मक या आकस्मिक है।

इसके बाद प्रशासक को कानूनी ढांचे के भीतर प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। संभावित उपायों में शामिल हैं:

- सहायता प्राप्त आवेदन केंद्र;
- बहुभाषी निर्देश;
- ऑफ़लाइन विकल्प;

- मोबाइल सेवा शिविर;
- पात्र लाभार्थियों की सक्रिय पहचान;
- स्थानीय संस्थानों के साथ अभिसरण;
- शिकायत निवारण तंत्र।

यदि नियम स्वयं अनुचित अपवर्जन पैदा करते हैं, तो प्रशासक को समस्या का दस्तावेजीकरण करना चाहिए और एकतरफा कानून का उल्लंघन करने के बजाय सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से उचित संशोधन की सिफारिश करनी चाहिए।

नैतिक संतुलन

हालाँकि, सहानुभूति का अर्थ नियमों में मनमानी छूट नहीं हो सकता। इनके बीच संतुलन होना चाहिए:

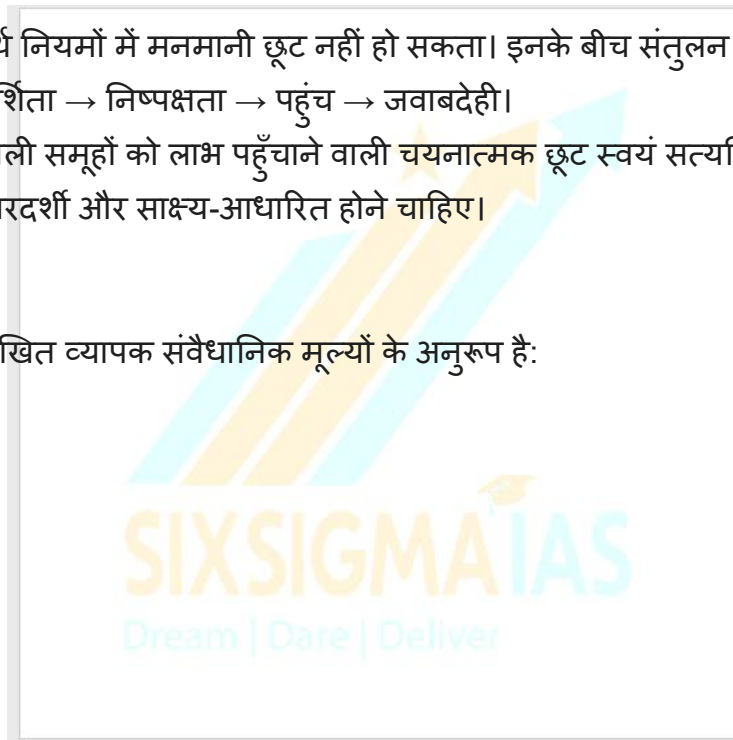
कानून का शासन → पारदर्शिता → निष्पक्षता → पहुंच → जवाबदेही।

राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूहों को लाभ पहुँचाने वाली चयनात्मक छूट स्वयं सत्यनिष्ठा का उल्लंघन होगी। इसलिए सुधार सामान्य, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित होने चाहिए।

संवैधानिक दृष्टिकोण

नैतिक दृष्टिकोण निम्नलिखित व्यापक संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है:

- समानता;
- गरिमा;
- सामाजिक न्याय;
- बंधुत्व;
- सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही।



प्रशासक की जिम्मेदारी केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि फाइल प्रक्रियात्मक रूप से पूर्ण है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि फाइल के अंतर्निहित सार्वजनिक उद्देश्य को महसूस किया जाए।

निष्कर्ष

सुशासन के लिए “अनुपालन संस्कृति” से “परिणाम-उन्मुख नैतिक संस्कृति” की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। प्रक्रियात्मक नियम मनमानी के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं, लेकिन सहानुभूति और प्रतिक्रियाशीलता यह सुनिश्चित करती है कि वे सुरक्षा उपाय न्याय में बाधा न बनें। इसलिए आदर्श प्रशासक न तो नियमों की अनदेखी करता है और न ही उनके पीछे छिपता है; बल्कि प्रशासक प्रणाली को अधिक सुलभ, निष्पक्ष और उन लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए कानूनी रूप से काम करता है जिनकी सेवा के लिए यह उद्देश्यित है।

करंट अफेयर्स — लद्दाख ग्लेशियल वाटर इनिशिएटिव

Q5. लद्दाख ग्लेशियल वाटर इनिशिएटिव यह दर्शाता है कि जलवायु-लचीला जल प्रशासन हमेशा बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चर्चा कीजिए कि यह पहल विकेंद्रीकरण, स्थानीय ज्ञान, अनुकूलनीय शासन और जलवायु लचीलेपन के सिद्धांतों को कैसे दर्शाती है। यदि ऐसे हस्तक्षेपों को बढ़ाया जाता है तो संबोधित किए जाने वाले पारिस्थितिक और प्रशासनिक चुनौतियों का भी परीक्षण कीजिए।

नमूना उत्तर

लद्दाख मौसमी प्रवाह में जल की प्रचुरता का विरोधाभास प्रस्तुत करता है लेकिन कृषि उपयोग के बिंदु पर गंभीर जल की कमी प्रस्तुत करता है। ठंडे-रेगिस्तानी वातावरण में, पर्याप्त हिमनद पिघला हुआ पानी चैनलों के माध्यम से बह सकता है जबकि खेती वाले क्षेत्र समय, इलाके और बुनियादी ढांचे में अंतर के कारण जल-तनावग्रस्त रहते हैं।

लद्दाख ग्लेशियल वाटर इनिशिएटिव ऐसी ही एक स्थानीय समस्या से उभरा है। चुचोट में, अधिकारियों ने स्टोक कांगड़ी ग्लेशियर द्वारा पोषित स्टोक गांव नाले से बहते पानी की पहचान की। मौजूदा सिंचाई अवसंरचना के माध्यम से प्रति दिन लगभग 90 मिलियन लीटर पानी को व्यवस्थित (चैनलाइज) किया गया, जिसमें लगभग 80 मिलियन लीटर इगू-फे नहर की ओर और दूसरा 10 मिलियन लीटर चुचोट की ओर निर्देशित किया गया। इस हस्तक्षेप ने कथित तौर पर 12 गांवों में 1000 एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई पहुंच का विस्तार किया।

रुपशू खारनाक ग्लेशियर धारा से जुड़ी एक बाद की बड़ी पहल का उद्देश्य औसतन लगभग 320 मिलियन लीटर प्रति दिन त्सो कर की ओर व्यवस्थित करना है, जिसका जल विस्तार पिछले दशक में काफी कम हो गया है।

विकेंद्रीकरण और स्थानीय ज्ञान

यह पहल केंद्रीय रूप से सोची गई मेगा-प्रोजेक्ट के बजाय एक स्थानीय शिकायत के साथ शुरू हुई। ग्राम-स्तरीय मांग ने एक प्रशासनिक प्रतिक्रिया दी, यह दर्शाता है कि विकेंद्रीकृत संस्थान उन समस्याओं की पहचान कैसे कर सकते हैं जो समग्र योजना डेटा में अदृश्य रह सकती हैं।

यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि प्रभावी शासन के लिए अक्सर संयोजन की आवश्यकता होती है:

स्थानीय ज्ञान + प्रशासनिक क्षमता + मौजूदा बुनियादी ढांचा।

अनुकूलनीय शासन

जलवायु परिवर्तन पर्वतीय क्षेत्रों की जल विज्ञान संबंधी विशेषताओं को बदल रहा है। हिमनद प्रणालियां स्थिर जलाशय नहीं हैं; उनके पिघलने के पैटर्न तापमान, वर्षा और ग्लेशियर की गतिशीलता के साथ बदल सकते हैं। इसलिए, जल शासन को निश्चित ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर होने के बजाय अनुकूलनीय बनना चाहिए। यह पहल निम्नलिखित द्वारा अनुकूलनीय शासन का प्रदर्शन करती है:

- एक मौजूदा जल स्रोत की पहचान करना;
- इसे मौजूदा नहरों से जोड़ना;
- जल वितरण को संशोधित करना;

- वास्तविक स्थानीय मांग का जवाब देना;
- और पारिस्थितिक बहाली के साथ जल सुरक्षा को एकीकृत करने का प्रयास करना।

जलवायु लचीलापन

यह हस्तक्षेप अत्यधिक पूंजी-गहन बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को कम करके और स्वाभाविक रूप से उपलब्ध मौसमी प्रवाह तक पहुंच में सुधार करके लचीलेपन को मजबूत कर सकता है।

हालाँकि, हिमनदों के पिघलने को असीमित या स्थायी रूप से बढ़ते जल संसाधन के रूप में नहीं माना जा सकता है।

त्वरित पिघलने से शुरू में अपवाह बढ़ सकता है लेकिन अंततः दीर्घकालिक ग्लेशियर भंडारण कम हो सकता है।

इसलिए, अवसंरचना नियोजन के साथ ग्लेशियर निगरानी और जलग्रहण प्रबंधन होना चाहिए।

पारिस्थितिक चिंताएं

ऐसी परियोजनाओं को बढ़ाने से कई प्रश्न उठते हैं:

- क्या विचलन डाउनस्ट्रीम पारिस्थितिक प्रवाह को बदल देगा?
- क्या आर्द्रभूमि या झील पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं?
- असामान्य रूप से कम पिघलने वाले वर्षों के दौरान क्या होता है?
- क्या अत्यधिक विचलन गांवों के बीच संघर्ष पैदा कर सकता है?
- क्या जल आवंटन पारदर्शी और सहभागी नियमों पर आधारित है?
- ग्लेशियर के व्यवहार में जलवायु-प्रेरित परिवर्तनों को योजना में कैसे शामिल किया जाएगा?

त्सो कर हस्तक्षेप विशेष रूप से जल निकायों को केवल भंडारण जलाशयों के रूप में मानने के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के साथ जल-सुरक्षा उद्देश्यों को संयोजित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

प्रशासनिक पाठ

यह पहल सार्वजनिक प्रशासन का एक व्यापक मॉडल प्रदान करती है जो निम्नलिखित पर आधारित है:

- प्रतिक्रियाशीलता;
- सामुदायिक भागीदारी;
- विकेंद्रीकृत समस्या पहचान;
- मितव्ययी नवाचार;
- मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग;
- अंतर-ग्राम समन्वय;
- पारिस्थितिक निगरानी;
- अनुकूलनीय योजना।

फिर भी प्रतिकृति (नकल) यांत्रिक नहीं होनी चाहिए। एक जलग्रहण क्षेत्र में जो काम करता है वह दूसरे स्थान पर समान रूप से काम नहीं कर सकता है क्योंकि हिमालयी और ट्रांस-हिमालयी जल विज्ञान प्रणालियों में काफी अंतर होता है।

निष्कर्ष

लद्दाख का अनुभव यह दर्शाता है कि जलवायु लचीलापन विशाल बुनियादी ढांचे का पर्याय नहीं है। संस्थागत प्रतिक्रियाशीलता, स्थानीय ज्ञान और मौजूदा बुनियादी ढांचे का बुद्धिमान उपयोग कभी-कभी अपेक्षाकृत कम हस्तक्षेप तीव्रता पर महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकता है। हालाँकि, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जल विज्ञान निगरानी, पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों, सहभागी आवंटन और ग्लेशियल जल संसाधनों की सीमित प्रकृति की मान्यता की आवश्यकता होती है। बड़ा सबक यह है कि जलवायु अनुकूलन को केवल बुनियादी ढांचे को समाधान मानने के बजाय प्रौद्योगिकी को संस्थानों और स्थानीय ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए।

